भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1217

बुधवार, 4 मई, 2016/14 वैशाख, 1938 (शक)

रोजगार के अवसर

1217. श्री रामदास अठावले:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में उन लोगों के प्रतिशत के संबंध में मूल्यांकन किया है जो क्रमशः कृषि, उद्योग, कारोबार और सेवा क्षेत्रों से अपनी आजीविका कमाते हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत दो वर्षों के दौरान उक्त क्षेत्रों में कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार मिला; और

(ग) विभिन्न क्षेत्रों में देश के युवाओं हेतु रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) और (ख): राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित किए रोजगार एवं बेरोजगारी के दो हालिया श्रम बल सर्वेक्षणों के परिणामों के अनुसार वर्ष 2009-10 तथा 2011-12 के दौरान क्षेत्रवार अनुमानित रोजगार नीचे दिया गया है:

प्रमुख क्षेत्र द्वारा कार्यबल	**2009-10**		**2011-12**	
	(%) में	व्यक्ति (करोड़ में)	(%) में	व्यक्ति (करोड़ में)
कृषि एवं अनुषंगी	53.15	24.74	48.90	23.18
उद्योग	21.48	10.00	24.25	11.50
सेवाएं	25.37	11.81	26.85	12.73
कुल कार्यबल	100.00	46.55	100.00	47.41

इसके अतिरिक्त श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने भारत में रोजगार में हुए परिवर्तन पर तिमाही त्वरित रोजगार सर्वेक्षण आयोजित किए। सर्वेक्षणों में श्रम गहन एवं निर्यात उन्मुखी इकाइयों को समाहित करते हुए

अर्थव्यवस्था के चुनिंदा क्षेत्रों को शामिल किया गया। इन सर्वेक्षणों के तहत, परिधान सहित वस्त्र, चमड़ा, धातु, ऑटोमोबाइल, रत्न एवं आभूषण, परिवहन, आईटी/बीपीओ और हथकरघा/पावरलूम क्षेत्र शामिल किए गए। सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, समस्त चुनिंदा क्षेत्रों में कुल मिलाकर अनुमानित रोजगार में वर्ष 2014 और 2015 के दौरान 11.48 लाख रोजगारों की निवल वृद्धि हुई है।

(ग) सरकार ने देश में रोजगार सृजन हेतु विभिन्न उपाय किए हैं- जैसे अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, व्यापक निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को तीव्रता से निष्पादित करना और अति लघु, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (एमजीनरेगा), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना। युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने हेतु लगभग 20 मंत्रालय 70 क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं संचालित करते हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए), कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में कौशलयुक्त बनाए गए व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	कौशलयुक्त बनाए गए व्यक्ति (लाख में)
2012-13	51.88
2013-14	76.37
2014-15	76.12
2015-16 (अक्तूबर, 2015 तक)	28.85

*****